साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 14-20 अगस्त 2023 वर्ष-9, अंक-18

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

पीएम ने सागर में रखी रविदास मंदिर की नींव, बोले

विकास में आगे बढ़ रहा एमपी पराधीनता सबसे बड़ा पाप

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश में सागर के बड़तूमा में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही थीं, तब रविदास ने मुगलों के कालखंड में कहा था- पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। पीएम ने कहा कि संत रविदास स्मारक और संग्रहालय की नींव एक ऐसे समय में पड़ी है जब देश ने अपने आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। अब अगले 25 वर्षों का अमृतकाल हमारे सामने है। अमृतकाल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं और अपने अतीत से सबक भी लें। संत रविदास के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है। एक डेढ़ साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। संत रविदास मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले है। शिवराज उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। मप्र अब विकास में काफी आगे बढ़ रहा है।

सागर की धरती पर सामाजिक समरसता के एक नए युग का उदय

किसानों को तीन समान किस्तों में छह हजार रुपए दिए जाएंगे

कैबिनेट का फैसला: किसानों के लिए शिवराज ने खोला खजाना

मध्यप्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार के बराबर सम्मान निधि

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के 83 लाख किसानों को दो हजार रुपए का सरकार उपहार देगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में अब चार के स्थान पर छह हजार रुपए मिलेंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। दो हजार रुपए की तीसरी किस्त देने पर लगभग एक हजार 700 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने किसानों को केंद्र सरकार के बराबर सम्मान निधि देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रतिवर्ष तीन समान किस्तों में छह हजार मिलते हैं। जबकि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में एक सितंबर 2020 से दो किस्तों में चार हजार रुपए दिए जा रहे थे।

अब किसानों को एक अप्रैल से 31 जुलाई, एक अगस्त से 30 नवंबर और एक दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में तीन समान किस्तों में छह हजार रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रदेश की ग्रामी पंचायत सचिव को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस पर 178.88 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। जिसे गौड खनिज मद से अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करया जाएगा। इस निर्णय से पंचायत सचिवों को अधिकतम 41 हजार 814 रुपए वेतन मिलेगा।

छतरपुर में नई तहसील सटई

शाजापुर में नवीन अनुभाग गुलाना और बालाघाट में नवीन अनुविभाग परसवाड़ा के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही छतरपुर जिले में नई तहसील सटई के गठन को स्वीकृति दी है। वहीं, ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद के रूप में गठित करने को स्वीकृति दी गई है।

किसानों को सुविधा

- 9.35 लाख अजाज किसानों को पांच हार्सपावर तक के कृषि पंप पर फ्री बिजली।
- अनारक्षित श्रेणी के किसानों को 51,896 के स्थान पर 3,750 रुपए बिजली बिल।
- मध्यप्रदेश के 11.91 लाख किसानों को ढाई हजार करोड़ रुपए की ब्याज मुक्ति।
- 30 लाख किसानों को खरीफ और रबी सीजन के लिए बिना ब्याज का कृषि ऋण।
- मप्र के किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी।
- प्राकृतिक आपदा से फसल को क्षति पहुंचने पर मिलने वाली राहत राशि में इजाफा।

सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं बना कर क्रियान्वित कर रही है। विगत वर्षों में किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों के खाते में 10 हजार प्रतिवर्ष सरकार ने जमा कराए है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 2 हजार रुपए की राशि बढ़ाई गई है। अब दोनों योजनाओं में प्रतिवर्ष किसानों को 12 हजार मिल रहे हैं।
कमल पटेल, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश

भोपाल के 3100 किसानों का खाता आधार से नहीं लिंक

इधर, भोपाल जिले में 3100 से अधिक किसानों ने अपने बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराए हैं, जबकि एक हजार से अधिक किसानों ने ई-केवाइसी भी नहीं कराया है। ऐसे में उन्हें सरकार से राशि नहीं मिल सकेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ ले रहे किसानों को अपना ई-केवाइसी एवं बैंक खाता आधार से लिंक करवाना है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में किसानों ने आधार से लिंक और केवायसी नहीं कराए है। आधार से लिंक नहीं होने की स्थिति में दोनों योजनाओं की किश्तों का भुगतान किसानों को नहीं किया जा सकेगा।

सोपा की रिपोर्ट, देशभर में बीते साल से ज्यादा उत्पादन की उम्मीद

सोयाबीन की बोवनी का आंकड़ा अनुमान से कम

- देश में 122 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुवाई होने का अनुमान
- मप्र और देश में बीते वर्ष से ज्यादा बोवनी का सोपा ने किया दावा

भोपाल। जागत गांव हमार

दि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सोपा) ने देश में सोयाबीन की बोवनी के ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं। अब तक देश में कुल 122 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी होने का अनुमान सोपा ने जताया है। मध्य प्रदेश और देश में बीते वर्ष से ज्यादा बोवनी की बात सोपा ने कही है। हालांकि सोपा की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा जो बोवनी के आंकड़े दिए हैं असल में उससे कम बोवनी सोपा ने मानी है। सोपा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में कुल 53.130 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है। जबकि सरकार का अनुमान 54.136 लाख हेक्टेयर का है। हालांकि सोपा ने माना है कि बीते वर्ष से ज्यादा सोयाबीन बोवनी हुई है। बीते वर्ष इस समय तक बुवाई का आंकड़ा सिर्फ 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा था। सोयाबीन बोवनी के मामले में मप्र सबसे आगे हैं।

सोयाबीन का उत्पादन सरकार की मदद करेग

देश में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। वहां 48.548 लाख हेक्टेयर में बोवनी हुई है। वहां भी बीते साल के मुकाबले सुधार हुआ है। देश में कुल मिलाकर सोयाबीन का बोवनी आंकड़ा बेहतर ही हुआ है। बीते वर्ष के 114.503 (सोपा) या 120.828 लाख हेक्टेयर के सरकारी आंकड़े के मुकाबले इस साल सोपा ने 122.394 और सरकार ने 124.110 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी का सर्वेक्षण दिया है। अब मौसम अनुकुल रहा तो इस लिहाज से इस वर्ष भी सोयाबीन का उत्पादन बेहतर रहने का अनुमान है। दरअसल आने वाला वर्ष आम चुनाव का होगा। ऐसे में खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर नियंत्रण लगाने में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन सरकार की मदद करेगा।

सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले-मध्यप्रदेश में वन, खनिज और जल सम्पदा का अपार भंडार

मध्यप्रदेश में देश के 13 प्रतिशत वन

-मुख्यमंत्री ने विभाग के नव निर्मित भवन का किया लोकार्पण

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में वन, खनिज और जल सम्पदा का अपार भंडार है। देश के 13 प्रतिशत वन मध्यप्रदेश में हैं। प्रदेश में अति-सघन वन लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा प्रदेश टाइगर स्टेट है, इसे टाइगर स्टेट बनाए रखने के लिए वन विभाग का हृदय से अभिनन्दन करता हूं। हम लेपर्ड और घड़ियाल स्टेट भी हैं। मुख्यमंत्री 180 करोड़ रुपए से नवनिर्मित तुलसी नगर स्थित वन भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वन कर्मियों और वन समितियों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। समारोह में वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम माधो सिंह, अपर मुख्य सचिव वन जेएन कंसोटिया, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख रमेश कुमार गुप्ता सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा वनकर्मी उपस्थित थे।

अर्थ-व्यवस्था का आधार वन

मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों की अर्थ-व्यवस्था का आधार वन ही हैं। अब प्रदेश में 785 टाइगर हो गए हैं, जो पहले से अधिक हैं। बारह सिंघा, सफेद बाघ भी हमारे यहाँ है। प्रदेश में वानिकी के क्षेत्र में नए रिकार्ड स्थापित किए गए हैं। बांस कलस्टर विकसित किए जा रहे हैं। पेसा नियम लागू करने में वन विभाग का सहयोग सराहनीय है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को चप्पल, जूता, कुप्पी, साड़ी और छाता दिए जा रहे हैं।

वनों को जनता के लिए बनाया वरदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जनता के लिए वनों को वरदान बनाया है। नवनिर्मित वन भवन पूर्ण हरित भवन है, जिसमें हवा, पानी और प्रकाश के संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। यह भवन नई ऊर्जा का संचार करेगा। विभाग को कार्य करने के लिए स्थान की कोई कमी नहीं रहेगी। वनों की सुरक्षा करने वालों की जिंदगी बेहतर करने की पूरी कोशिश होगी। वन्य-प्राणियों का संरक्षण बहुत पुण्य का कार्य है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में अधिक से अधिक वन स्थापित हों जिससे प्रदेश में आक्सीजन का उत्सर्जन बड़े स्तर पर हो, प्रदेश दुनिया में ऑक्सीजन हब बन जाए।

वनवासियों का गहरा संबंध

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन और वनवासियों का गहरा संबंध है। वनों के माध्यम से उनकी जिंदगी में खुशहाली पैदा करने की कोशिश होगी। वनों के बिना इंसान की जिंदगी नहीं चल सकती है। यह धरती सभी जीव-जंतुओं की है। इसे बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। मध्यप्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण में बेहतर कार्य हुआ है।

आर्थिक सहायता का प्रावधान

वन मंत्री ने कहाकि मुख्यमंत्री के सान्निध्य में वन विभाग में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है। मुख्यमंत्री प्रतिदिन एक पौधा जरूर लगाते हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। वन विभाग सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। वन समितियों को पिकअप वाहन सौंपे गए हैं। वन्य-प्राणियों के कारण मृत्यु पर आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।

विभाग वनों के संरक्षण के लिए समर्पित

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख रमेश कुमार गुप्ता ने कहा कि वन विभाग की जनहितकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश में वनों के क्षेत्र में बेहतर काम करने की कोशिश लगातार बनी रहेगी। अपर मुख्य सचिव वन कंसोटिया ने कहा कि विभाग वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित है। वन भवन से सभी गतिविधियां संचालित होंगी और हम पूरे देश में अव्वल रहेंगे।

शासकीय कार्यालय और प्रतिष्ठान परिसर में भी होगा पौधरोपण

पौधरोपण महाअभियान प्रदेश व्यापी 13 से 15 अगस्त तक

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्य शासन द्वारा अंकुर कार्यक्रम में 13 से 15 अगस्त 2023 तक प्रदेश व्यापी महा पौध-रोपण अभियान चलाया जाएगा। नागरिकों, समुदायों, शासकीय विभागों और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से संचालित होने वाले अभियान के लिए प्रमुख सचिव पर्यावरण गुलशन बामरा ने सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि आम जन की सुविधा के लिये सभी शहरों और गांवों में पौध-रोपण के लिए स्थल अंकुर उपवन चिन्हित करें और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करें। जिलों के अशासकीय, समुदाय आधारित और निजी संगठनों को अभियान से जोड़ते हुए उनके परिसर एवं अन्य उचित स्थलों पर पौध-रोपण का भी कार्य किया जा सकता है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति- पूर्व महा अभियान की तर्ज पर प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी स्टेक होल्डर को शामिल करते हुए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। समिति 13 से 15 अगस्त तक पौध-रोपण अभियान का सतत समन्वय, अनुश्रवण और मॉनिटरिंग करने के साथ अंकुर कार्यक्रम की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करेगी।

होगा पौध-रोपण- प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय भवन, सार्वजनिक उपक्रम, औद्योगिक संस्थान, निगम-मंडल कार्यालयों के प्रांगण, स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी, छात्रावास, पंचायत परिसर आदि में भी पौध-रोपण किया जाएगा।

पौधों की व्यवस्था

पौधों की व्यवस्था संबंधित व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी। वन, उद्यानिकी और कृषि विभाग की नर्सरी में उपलब्ध पौधों का उपयोग प्रचलित नियमानुसार किया जाएगा। रोपित पौधों की सुरक्षा, सिंचाई और देख-भाल की जिम्मेदारी पौध-रोपण करने वाले व्यक्ति,संगठन या शासकीय संस्था की होगी।

अब तक 66 लाख पंजीयन

पौध-रोपण को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रदेश में जन भागीदारी से पहले 1 से 5 मार्च 2022, 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022 तथा 19 फरवरी 2023 को प्रदेश स्तरीय पौध-रोपण महा अभियान संचालित किया गया है। अंकुर कार्यक्रम में अब तक 16 लाख से अधिक नागरिकों द्वारा 66 लाख से अधिक पौध-रोपण का पंजीयन किया जा चुका है।

पंजीयन वायुदूत-अंकुर एप पर

अभियान से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पौध-रोपण का पंजीयन अंकुर कार्यक्रम के वायुदूत-अंकुर एप पर करना होगा। रोपित पौधे की फोटो वायुदूत एप पर अपलोड करनी होगी। एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रतिभागियों द्वारा पौध-रोपण के 30 दिन बाद वायुदूत अंकुर एप पर रोपित पौधे का द्वितीय फोटो अपलोड करने पर सहभागिता प्रणाम-पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। पौध-रोपण के 6 माह बाद पौधे का तृतीय फोटो अपलोड करना होगा।

कृषि मंत्री पटेल ने कहा-खेती बन रही लाभ का धंधा

तेंदूपत्ता संग्राहकों को हर सुविधाएं उपलब्ध मिल रहीं

भोपाल। जागत गांव हमार

हरदा जिले के कृषि उपज मंडी टिमरनी में तेंदूपत्ता संग्राहकों को साड़ी, छाता, चरण पादुका व पानी की बोतलें वितरित की गई। वन मंत्री डॉ. विजय शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय बढ़ाने तथा उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। विगत वर्षों में तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार के समग्र प्रयासों से खेती अब लाभ का धंधा बन रही है। क्षेत्रीय विधायक संजय शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेन्द्र शाह, उपाध्यक्ष दर्शनसिंह गेहलोद, नगर परिषद अध्यक्ष देवेन्द्र भारद्वाज व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर मुकाती सहित अन्य जन-प्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं बना कर क्रियान्वित कर रही है। विगत वर्षों में किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों के खाते में 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष सरकार ने जमा कराए है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 2 हजार रुपए की राशि बढ़ाई गई है। अब दोनों योजनाओं में प्रतिवर्ष किसानों को 12 हजार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूंग की फसल की सिंचाई के लिये तवा नहर परियोजना से भरपूर पानी मिलने से हरदा व आसपास के क्षेत्र में किसानों को काफी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिले, इसके लिये फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी सरकार ने समय-समय पर वृद्धि की है।

कृषक बहुद्देशीय केंद्र बनवाने की घोषणा

कृषि मंत्री ने सम्मेलन में 2 करोड़ लागत से कृषक बहुद्देशीय केन्द्र बनवाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने टिमरनी विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में कृषक बहुद्देशीय टीन शेड का निर्माण कराने तथा हरदा, टिमरनी, सिराली व खिरकिया की मंडियों में अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए फायर ब्रिगेड स्वीकृत करने की घोषणा भी की।

मुगल बादशाहों के दरबार से लेकर खाड़ी देशों तक मशहूर थी हमारे पान की मिठास

अब पान उत्पादक किसानों की लागत भी नहीं निकल रही

हाल-बेहाल

मध्यप्रदेश में खत्म हो रही पान की विरासत

रतलाम। अपने देश के साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में मशहूर चौरानी का नाम पान के शौकीनों ने जरूर सुना होगा। मध्यप्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर चौराना गांव में इस पान की पैदावार होती है। अब इसकी खेती में हो रहे लगातार घाटे ने इस विरासत को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है। वजह है- पान की खेती में लागत और मुनाफे का अंतर कम होता जा रहा है। दो साल पहले तक हर किसान को पान की प्रति कतार के हिसाब से 5 हजार रुपए मिल जाते थे, जो कि अब कम होकर मात्र 2 से 3 हजार रह गया है। चौरानी पान की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि ऐसे में मेहनत और लागत लगाने के बाद भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

किसान की जुबानी, चौरानी पान की कहानी

हमारे देश में प्रसिद्ध बनारसी पान, मद्रासी, कपूरी, सुहागपुरी, रामटेकी और महोवा पान से अलग मालवा के चौरानी पान की अपनी एक अलग ही पहचान है। जैसे ये सभी पान की किस्में अपने-अपने क्षेत्र के नाम से मशहूर है, इसी तरह रतलाम के चौरानी पान का नाम भी चौराना गांव के नाम से पड़ा है। चौराना गांव में इस खास पान की खेती करने वाले 8-10 किसान ही बचे हैं, जो सालों से चली आ रही पारंपरिक खेती और विरासत को संभाले हुए हैं। मुगल काल से ही इस गांव में तंबोली चौरसिया समाज के लोग पान की खेती कर रहे हैं। यह खेती 300 वर्ष से जारी है। शुरुआती दौर में मेरे पूर्वजों ने रिश्तेदारों के यहां से पान की बेल लाकर गांव के छोटे से हिस्से में खेती शुरू की थी। धीरे-धीरे गांव में 20 बीघा क्षेत्र में इसकी खेती होने लगी। आसपास के शहरों में यह चौरानी पान के नाम से मशहूर होने लगा। मुगल काल के अंतिम दौर में यहां के पान की चर्चा दिल्ली दरबार तक पहुंची। साथ ही अन्य बड़े शहर जैसे कराची, लाहौर, लखनऊ, वाराणसी और कोलकाता में भी यहां के पान का स्वाद पहुंचा।

पांच महीने की फसल

5 महीने की कड़ी मेहनत से चौरानी पान की फसल तैयार होती है। चौरानी पान जितना प्रसिद्ध है, उतनी ही मेहनत इसकी खेती में करनी पड़ती है। मिट्टी की गहरी जुताई करके करीब 1 फीट ऊंचा बेड (मेढ़) बनानी होती है। इसके बाद बेड पर पान की बेल की कलम डेढ़ बाय डेढ़ की दूरी पर लगाई जाती है। गर्मी का मौसम होने की वजह से सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ती है। कीट और मौसम की मार से बचाने के लिए इसे छायादार नेट हाउस में लगाया जाता है। नेट हाउस की सुविधा नहीं होने पर किसान मिलजुल कर बांस-बल्ली और नेट का उपयोग कर नेट हाउस तैयार करते हैं। पान के स्वाद और गुणवत्ता पर कोई असर ना हो इसके लिए किसी भी प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

खो रही चौरानी पान की विरासत

चौराना गांव में पहले करीब 20 बीघा जमीन पर चौरसिया समाज के 80 से अधिक किसान पान की खेती किया करते थे। अब मात्र 8 से 10 किसान ही पान की खेती कर रहे हैं। विडंबना यह रही कि अधिकांश किसानों के पास खुद की जमीन नहीं थी। जिनके पास जमीन थी वह भी बेचकर शहर चले गए। पहले ये सभी किसान जमीन लीज पर लेकर पान की खेती करते थे। बीते कुछ सालों में जमीन की लीज के रेट बढ़ने के कारण पान की खेती लीज की जमीन पर करना महंगा हो गया है। गांव में अब सिंचित एक बीघा जमीन लीज पर लेने के लिए 20 हजार वार्षिक तक खर्च करना पड़ रहा हैं।

लोन भी नहीं ले पाते पान की खेती करने वाले

किसान महेंद्र चौरसिया बताते हैं कि मैंने अपने तीनों बेटों को इंदौर निजी कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया है। जब तक हो सकेगा, वे खेती करेंगे और फिर गांव छोड़कर अपने बेटों के पास चले जाएंगे। उनका कहना है कि लीज की जमीन होने की वजह से कृषि और उद्यानिकी विभाग की नजरों में ये लोग किसान हैं ही नहीं। इन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर उद्यानिकी विभाग की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं का कोई लाभ प्राप्त नहीं मिलता है। इन्हें पान की खेती के लिए कोई सहकारी सोसायटी या बैंक लोन भी नहीं देती है। ना ही इन्हें किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया है। लगातार हो रहे नुकसान की वजह से अब किसान पान की खेती छोड़ रहे हैं। गांव में गिनती के ही कुछ लोग हैं, जो इस विरासत को संभाल रहे हैं। उनका भी मन अब इस खेती से उचट गया है।

सेवन से पाचन की प्रक्रिया बेहतर

पान का इस्तेमाल इसके औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी किया जाता है। भोजन के बाद पान के सेवन से पाचन की प्रक्रिया बेहतर होती है। चौरानी पान के सेवन से गले का इन्फेक्शन और खराश दूर होती है। पान का उपयोग औषधि के रूप में करने से उदर, यकृत और श्वास रोग में राहत मिलती है। आयुर्वेद के जानकारों के मुताबिक चौरानी पान में औषधीय गुण बाकी क्षेत्रों के पान की अपेक्षा अधिक होता है।

ऐसे समझें पान की खेती में घाटे का गणित

पहले किसानों के समूह होने की वजह से अधिक मात्रा में पान की कतार तैयार करते थे। इससे अच्छा उत्पादन मिल जाता था। सभी किसानों का उत्पादन एक साथ कम लागत में दिल्ली और मुंबई की मंडी तक पहुंचाया जाया करता था। इससे प्रत्येक किसान को अच्छा मुनाफा हासिल हो जाया करता था। खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यहां के पान की मांग होने से अच्छे दाम मिलते थे। किसान महेंद्र चौरसिया ने बताया कि उनके पास पान की 200 फीट लंबी 23 कतारें हैं।

तीन लाख रुपए का खर्च

महेंद्र ने बताया कि किसान लीज पर 1-2 बीघा जमीन लेते हैं। इसी जमीन पर पनवाड़ी तैयार की जाती है। एक बीघा जमीन पर पनवाड़ी तैयार करने में 3 लाख रुपए का खर्च आता है। इसमें डेढ़ से दो लाख रुपए प्रतिवर्ष के पान का उत्पादन होता है। प्राकृतिक आपदा और बीमारियों से सुरक्षित रहने पर तीसरे और चौथे वर्ष भी पान का उत्पादन लिया जा सकता है। पनवाड़ी में तैयार की गई पान की कतार दो से तीन किसान मिलकर तैयार करते हैं। औसतन एक किसान के हिस्से में 20 से 30 कतारें आ जाती हैं।

घट गया किसानों का मुनाफा

पान की कतारों को अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किसान आपस में बांट लेते हैं। तीन से चार साल पहले तक 200 फीट लंबी पान की एक कतार से सीजन में 5 हजार तक का लाभ मिल जाता था। लेकिन अब पान का एक्सपोर्ट बंद हो जाने की वजह से यह मुनाफा 2000 से 3000 रुपए तक ही रह गया है। अब किसानों की मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। पहले पान के पत्तों का उत्पादन अधिक मात्रा में होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगती थी, लेकिन अब पान मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ गया है।

पान की खेती को बचाने के लिए प्रपोजल भेजा

गांव के समाजसेवी तूफान सिंह ने बताया कि गांव के जनप्रतिनिधियों के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल से मिलकर पान की खेती को संरक्षित खेती घोषित करने और लीज पर खेती करने वाले किसानों को योजनाओं का लाभ देने की मांग की है। कृषि मंत्री ने भी इस मांग को पूरा करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की बात कही है। वहीं, उप संचालक कृषि विभाग विजय चौरसिया ने बताया कि पान की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष प्रोजेक्ट का प्रपोजल वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। इसके तहत किसानों को पान की खेती करने के लिए शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

फसल बीमा: किसानों से ज्यादा बीमा कंपनियों का फायदा

संजय माकवे, वरिष्ठ पत्रकार

प्राकृतिक आपदा के कारण खेती में फसलों को हरसाल बडा नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में फसलों को हुये नुकसान के लिये किसानों को मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है। मुआवजे के लिये केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कृषि बजट में हरसाल लगभग 20 से 25 हजार करोड रुपयों का प्रावधान करती है। सरकार को चाहिये था कि वह टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसी पारदर्शी योजना बनाती जिससे सभी प्रभावित किसानों को सीधा लाभ मिल सके। लेकिन सरकार ने मुआवजा देने के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम से ऐसी योजना बनाई कि, जिससे किसानों को नही, बीमा कंपनियों को लाभ मिल रहा है।

किसानों को आपदा से फसल नुकसान से राहत दिलाने के लिए सरकार ने मुआवजा देने के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम से ऐसी योजना बनाई, लेकिन इस योजना से किसानों को कम औरबीमा कंपनियों को ज्यादा लाभ मिल रहा है। जिन कंपनियों का खेती से दूर-दूर तक संबंध नही है, ऐसी कंपनियों को केवल मुआवजा बांटने के लिये बड़ा लाभ पहुंचाया जा रहा है। जो किसानों का हक है, उसे फसल बीमा कंपनियों के हवाले किया जा रहा है।

फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देने के लिये 7 साल में किसानों का 28847 करोड़ रुपये मिलाकर केंद्र और राज्य सरकारों ने 1 लाख 96 हजार 228 करोड रुपयें फसल बीमा कंपनियों को सौपे, जिसमें से स्वीकृत दावों के अनुसार किसानों को 1 लाख 36 हजार 154 करोड रुपये मुआवजा दिया गया। फसल बीमा कंपनियों को केवल मुआवजा बांटने के लिये 7 साल में 60 हजार 73 करोड रुपये मिले हैं।

इन सालों में 46.92 करोड़ किसान फसल बीमा योजना में शामिल हुये। जिसमें से केवल 12.98 करोड किसानों को मुआवजा मिला है। इसमें करोड़ों किसानों को बहुत कम मुआवजा मिला। 33.94 करोड किसानों को कुछ भी नही मिला। उल्टा इन किसानों को हरसाल जमा किये गये बीमा हप्ते का नुकसान उठाना पडा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई है। 2016-17 से 2022-23 के उपलब्ध सरकारी आंकडे स्पष्ट करते है कि फसल बीमा कंपनियों ने प्रतिवर्ष 8 से 10 हजार करोड रुपये के हिसाब से 7 साल में 60 हजार करोड रुपये लूटे हैं। महाराष्ट्र से 12484 करोड रुपये, राजस्थान से 10524 करोड रुपये, मध्यप्रदेश से 9777 करोड रुपये और गुजरात से 6628 करोड रुपये लूटे गये हैं।

ऐसा दिखाई देता है कि इस बड़ी लूट के लिये फसल बीमा कंपनियां किसान मतदाताओं को प्रभावित करने के इरादे से चुनाव में सरकार को लाभ पहुंचाने का काम करती है। केवल चुनावी सालों में मुआवजा बांटने काम किया जाता है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2017-18 में 5894 करोड रुपये, वर्ष 2019-20 में 5812 करोड रुपये और वर्ष 2020-21 में 7791 करोड रुपये मुआवजा दिया गया है। जो उस वर्ष में कंपनियों को प्राप्त बीमा से ज्यादा है। मध्यप्रदेश में नवम्बर 2018 में विधानसभा चुनाव, मई 2019 में लोकसभा के चुनाव और नवम्बर 2020 में 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुये है।

जबकि मध्यप्रदेश में कुल 6 सालों में कंपनियों को 35506 करोड़ रुपये बीमा प्राप्त हुआ। इसमें से किसानों को 25729 करोड रुपयें मुआवजा दिया गया और कंपनियो ने 9777 करोड रुपये लूटे है। इसका अर्थ यह भी है कि दूसरे सालों में मुआवजा नही के बराबर मिला।

अब महाराष्ट्र सरकार एक रुपये में फसल बीमा योजना शुरू कर रही है। इसमें भलेही किसानों का लाभ दिखाई देता है लेकिन यहां किसानों का बीमा हप्ता कृषि बजट में कटौती करके ही कंपनियों को दिया जाना है। इसलिये इससे भी किसानों को अंतिमत- नुकसान ही होगा।

सरकार भलेही दावा करती है कि वह किसानों को लूटनेवाले दलालों को हटाना चाहती है लेकिन यहां सरकारने खुद कारपोरेट दलाल पैदा किये है। जो केवल मुआवजा बांटने के लिये हरसाल 10 हजार करोड रुपये कमाते है। इस लूट में भी निजी बीमा कंपनियां अग्रसर है। पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल ने पहले ही खुद को योजना से बाहर किया है। अब दावों के कम भुगतान के कारण आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगना और झारखंड ने भी इस योजना को बंद किया है।

सरकार के किसान विरोधी नीतियों के चलते खेती में पहले से ही किसानों का शोषण हो रहा है। फसलों को न्याय्य दाम देने और लागत खर्च में कंपनियों द्वारा होनेवाली लूट रोकने के लिये सरकार ने कोई उपाय नही किये बल्कि किसानों का शोषण करने के लिये उद्योगपतियों और व्यापारियों को लूट की खुली छूट दी गई है। और अब प्राकृतिक आपदा में नुकसान भरपाई देने का काम कंपनियों को सौपकर केंद्र सरकार बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है।

सैद्धांतिक रुपसे नुकसान भरपाई देने के लिये बीमा योजना लागू करना गलत है। जिसके कारण कृषि बजट का बडा हिस्सा हरसाल कंपनियों को मिलता है और किसानों को नुकसान उठाना पडता है। मुआवजा बांटने के लिये बीमा कंपनियों को एजेंट बनाने के बजाए कृषि विभाग की मदद से सीधा तरीका अपनाया होता तो देश के किसानों को 60 हजार करोड रुपये ज्यादा मिल सकते थे। बशर्ते कि कृषि विभाग का भ्रष्टाचार दूर करना होगा।

कृषि में गेम चेंजर साबित हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग

क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक ने विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी है और कृषि भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में, कृषि में क्लाउड कंप्यूटिंग अद्गष्द्धड्डश्व्यश्द्द4 के एकीकरण ने उल्लेखनीय परिवर्तन लाए हैं, जिससे किसानों और कृषि व्यवसायों को दक्षता, उत्पादकता और स्थिरता में सुधार के नए अवसर मिले हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा, इसकी प्रमुख विशेषताओं और कृषि क्षेत्र को इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले महत्वपूर्ण लाभों की पड़ताल करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट पर डेटा और एप्लिकेशन के भंडारण, प्रसंस्करण और साझा करने के योग्य बनाती है, जिससे ऑन-प्रिमाइसेस बुनियादी ढांचे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। स्थानीय सर्वर या भौतिक हार्डवेयर पर निर्भर रहने के बजाय, क्लाउड-आधारित सेवाओं को थर्ड पार्टी प्रदाताओं द्वारा होस्ट और रखरखाव किया जाता है, जो इंटरनेट कनेक्शन के साथ कभी भी और कहीं भी पहुंच योग्य होती हैं।

क्लाउड कंप्यूटिंग मौसम के पैटर्न, मिट्टी की गुणवत्ता, फसल प्रदर्शन और बाजार के रुझान सहित बड़ी मात्रा में कृषि डेटा के सुरक्षित भंडारण की सुविधा प्रदान करती है। किसान कई उपकरणों से वास्तविक समय में इस डेटा तक पहुंच सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। क्लाउड सेवाएं स्केलेबल समाधान प्रदान करती हैं, जो कृषि व्यवसायों की गतिशील जरूरतों को समायोजित करती हैं, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। किसान अपनी डेटा भंडारण और प्रसंस्करण क्षमताओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आसानी से ऊपर या नीचे कर सकते हैं।

क्लाउड प्रौद्योगिकी कृषि आपूर्ति श्रृंखला के भीतर हितधारकों के बीच निर्बाध सहयोग को बढ़ावा देती है। किसान, शोधकर्ता, कृषिविज्ञानी और खरीदार आसानी से डेटा, अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम विधियों को साझा कर सकते हैं, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा दे सकते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण अग्रिम निवेश की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। इसके बजाय, उपयोगकर्ता उन सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं जिनका वे उपयोग करते हैं, जिससे छोटे पैमाने के किसानों को किफायती लागत पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने में मदद मिलती है।

प्रतिष्ठित क्लाउड सेवा प्रदाता संवेदनशील कृषि डेटा को उल्लंघनों और साइबर हमलों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करते हैं। यह डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करता है, जो आधुनिक कृषि पद्धतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कृषि में इस तकनीक का बहुत लाभ होता है। किसान अगर इस तकनीक के अनुसार अपनी फसलों की पैदावार को सुनिश्चित करते हैं तो बहुत आसानी से अच्छी पदावर को हासिल कर सकते हैं साथ ही बाज़ार की पूरी जानकारी को प्राप्त कर अच्छा मुनाफा ही भी कमा सकते हैं। हम इस तकनीक से निम्न कृषि लाभ अर्जित कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग किसानों को मौसम पूर्वानुमान, मिट्टी की स्थिति और फसल स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण डेटा तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करती है। विभिन्न स्रोतों और सेंसरों से डेटा को एकीकृत करके, सटीक कृषि पद्धतियाँ अधिक सुलभ और प्रभावी हो जाती हैं। किसान सिंचाई, उर्वरक और कीट नियंत्रण का सटीक प्रबंधन कर सकते हैं, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित कर सकते हैं और अपशिष्ट को कम कर सकते हैं। डेटा-संचालित निर्णयों से फसल की पैदावार अधिक होती है, गुणवत्ता में सुधार होता है और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। क्लाउड-आधारित रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग प्रौद्योगिकियां किसानों को दूर से अपनी फसलों की निगरानी करने में सक्षम बनाती हैं। कैमरे और सेंसर से लैस ड्रोन उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां खींच सकते हैं, जिससे फसल के तनाव, बीमारियों या पोषक तत्वों की कमी की जल्द पहचान करने में मदद मिलती है। यह लक्षित हस्तक्षेपों की अनुमति देता है, व्यापक स्पेक्ट्रम रसायनों की आवश्यकता को कम करता है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग कृषि आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों के बीच सहज समन्वय की सुविधा प्रदान करती है। बीज आपूर्तिकर्ताओं से लेकर वितरकों और खुदरा विक्रेताओं तक, सभी लाभ लेने वाले आसानी से जानकारी साझा कर सकते हैं। यह बढ़ी हुई कनेक्टिविटी इनपुट और उत्पादों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करती है, नुकसान को कम करती है और किसानों के लिए लाभप्रदता बढ़ाती है।

क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध ऐतिहासिक और वास्तविक समय के बाज़ार डेटा का विश्लेषण करके, किसान फसल चयन और मूल्य निर्धारण के बारे में रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं। वे उभरते रुझानों की पहचान भी कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने उत्पादन को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त सुनिश्चित हो सके। मौसम डेटा और पूर्वानुमानों तक क्लाउड-आधारित पहुंच के साथ, किसान चरम मौसम की घटनाओं के लिए सक्रिय रूप से योजना बना सकते हैं और तदनुसार अपनी खेती की प्रथाओं को अनुकूलित कर सकते हैं।

क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक कृषि क्षेत्र के लिए एक गेम-चेंजर के रूप में उभरी है, जो किसानों और कृषि व्यवसायों को डेटा-संचालित, टिकाऊ और कुशल प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बनाती है। क्लाउड की शक्ति का लाभ उठाकर, सटीक खेती एक वास्तविकता बन जाती है, जिसमें किसान वास्तविक समय के डेटा और बाजार अंतर्दृष्टि के आधार पर सही निर्णय लेते हैं।

कम वर्षा: धान उपज पर खतरे का बादल

जून और जुलाई में देश के कई हिस्सों में हुई कम वर्षा के चलते धान के उत्पादन पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, उड़ीसा के कटक स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि मौसम वैज्ञानिक देबाशीष जेना ने डीटीई को बताया कि उत्पादन तभी प्रभावित होगा जब मानसून कोर जोन में मानसून खराब होगा, क्योंकि वहां फसल ज्यादातर वर्षा पर आधारित होती है।

भारत में कोर मानसून क्षेत्र पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इसे एक कृषि क्षेत्र के रूप में सीमांकित करता है जहां फसल ज्यादातर वर्षा पर निर्भर होती है।

वर्तमान में 717 में से कुल 239 जिले ऐसे हैं जहां वर्षा कम (डिफिशिएंट) या बहुत कम (लार्ज डिफिशिएंट) हुई है। इनमें से अधिकांश पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल के पूर्वी मौसम उपविभागों में केंद्रित हैं। अधिक चिंता की बात यह है कि यह विस्तार भारत के चावल उत्पादन बेल्ट के साथ ओवरलैप होता है।

अगस्त की शुरुआत में ही मानसून ब्रेक पर है। मानसून ट्रफ जब उत्तर की ओर खिसक जाता है तब मानसून ब्रेक होता है। इस मानसून ब्रेक के कारण हिमालय की तलहटी और पूर्वी भारत में वर्षा होती है और देश के अन्य भागों में वर्षा गतिविधि कम हो जाती है।

मानसून ब्रेक का इस खरीफ सीजन में धान के उत्पादन के लिए आखिर क्या मतलब है?

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप के डेटा से पता चलता है कि 2022 की तुलना में बुआई क्षेत्र में वास्तव में लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या अधिक बुआई क्षेत्र का मतलब अतिरिक्त समग्र उपज है?

डीटीई ने पहले उत्तर प्रदेश के किसानों से बात की थी। श्रावस्ती जिले के किसानों को भारी नुकसान हुआ था क्योंकि जून 2023 में कम बारिश के कारण उनकी नर्सरी नष्ट हो गई थी।

विकट परिस्थितियों से बचने के लिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों को छोटी अवधि के धान के संस्करण अपनाने के लिए सलाह जारी की थी, जो सामान्य 180 दिनों के बजाय 125 दिनों में पक जाते हैं।

जेना के अनुसार, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आईएमडी फसल चक्र के विभिन्न चरणों को ट्रैक कर सके।

उन्होंने कहा प्रजनन चरण फसल चक्र का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। प्रजनन चरण के दौरान चावल को खेतों में 10 सेंटीमीटर पानी की गहराई की आवश्यकता होती है और पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगस्त की बारिश (आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार) से इस संबंध में मदद मिलनी चाहिए।

आकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों के रकबे में सुधार नजर आया

देश में दलहन फसलों के आ रही गिरावट में आई कमी

खरीफ फसल का रकबा बढ़कर 915 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

खरीफ फसल का रकबा बढ़कर 915 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा। कृषि मंत्रालय ने खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्रों के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। इन आकड़ों के अनुसार इस सप्ताह खरीफ फसलों के रकबे में सुधार नजर आया है। पिछले सप्ताह खरीफ फसल के रकबे में मामूली 0.30 फीसदी की गिरावट देखी गई थी। लेकिन इस सप्ताह खरीफ फसलों के रकबे में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। इसके रकबे में वृद्धि की वजह दलहन फसलों के आ रही गिरावट में कमी आना है। वहीं तिलहन फसल जैसे सोयाबीन की फसल के रकबे में चार फीसदी इजाफा हुआ है। इसके अलावा मोटे अनाज, गन्ना व धान की बुआई में वृद्धि हुई हैं, जबकि कपास के रकबे में मामूली गिरावट देखी गई हैं। आंकड़ों के अनुसार अनुमानित कवरेज क्षेत्र 1091.73 लाख हेक्टेयर है, लेकिन अभी तक कुल 915.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलें बोई गई हैं। वहीं पिछले वर्ष 2022 में कुल 911.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी हुई थी। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बोवनी क्षेत्र में कुल 3.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

धान: पिछले वर्ष की इसी अवधि (273.73 लाख हेक्टेयर) की तुलना में चावल के अंतर्गत लगभग 283.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज दर्ज किया गया है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 9.27 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र कवर किया गया है। छत्तीसगढ़ (6.37 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (4.36 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (2.74 लाख हेक्टेयर), झारखंड (1.56 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (1.51 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (0.48 लाख हेक्टेयर), गुजरात (0.42 लाख हेक्टेयर), राजस्थान (0.27 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.18 लाख हेक्टेयर), पंजाब (0.07 लाख हेक्टेयर) राज्यों में अधिक बुवाई कि रिपोर्ट मिली हैं।

दलहन:-

पिछले वर्ष की इसी अवधि (117.87 लाख हेक्टेयर) की तुलना में दलहन के अंतर्गत लगभग 106.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज दर्ज किया गया है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 10.98 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र कवर किया गया है। राजस्थान (1.17 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (0.55 लाख हेक्टेयर), जम्मू-कश्मीर (0.08 लाख हेक्टेयर) और पश्चिम बंगाल (0.02 लाख हेक्टेयर) राज्यों में अधिक बुवाई कि रिपोर्ट मिली हैं। वही कर्नाटक (3.97 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (3.03 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (2.53 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (0.92 लाख हेक्टेयर), छत्तीसगढ़ (0.54 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (0.39 लाख हेक्टेयर), झारखंड (0.34 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.33 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (0.24 लाख हेक्टेयर), बिहार (0.23 लाख हेक्टेयर राज्यों से कम बोवनी की सूचना मिली है।

मोटे अनाज:

पिछले वर्ष की इसी अवधि (162.43 लाख हेक्टेयर) की तुलना में लगभग 164.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाज का कवरेज दर्ज किया गया है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 1.77 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र कवर किया गया है। मध्य प्रदेश (1.66 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (1.02 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (0.39 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.29 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (0.22 लाख हेक्टेयर), झारखंड (0.10 लाख हेक्टेयर) राज्यों में अधिक बुवाई कि रिपोर्ट मिली हैं। वही महाराष्ट्र (1.23 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (0.27 लाख हेक्टेयर), बिहार (0.18 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (0.11 लाख हेक्टेयर), पश्चिम बंगाल (0.08 लाख हेक्टेयर), उत्तराखंड (0.06 लाख हेक्टेयर) जम्मू-कश्मीर (0.05 लाख हेक्टेयर) राज्यों से कम बोवनी की सूचना मिली है।

तिलहन:

पिछले वर्ष की इसी अवधि (175.10 लाख हेक्टेयर) की तुलना में तिलहन के अंतर्गत लगभग 179.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज दर्ज किया गया है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 4.47 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र कवर किया गया है। मध्य प्रदेश (4.69 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (1.03 लाख हेक्टेयर), गुजरात (1.02 लाख हेक्टेयर) राज्यों में अधिक बुवाई कि रिपोर्ट मिली हैं। वही महाराष्ट्र (0.79 लाख हेक्टेयर), राजस्थान (0.78 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (0.32 लाख हेक्टेयर) आंध्र प्रदेश (1.93 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (1.58 लाख हेक्टेयर), छत्तीसगढ़ (0.19 लाख हेक्टेयर), बिहार (0.17 लाख हेक्टेयर), तमिलनाडु (0.15 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (0.09 लाख हेक्टेयर) राज्यों से कम बोवनी की सूचना मिली है।

गन्ना: पिछले वर्ष की इसी अवधि (54.67 लाख हेक्टेयर) की तुलना में लगभग 56.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने का कवरेज दर्ज किया गया है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 1.39 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र कवर किया गया है। उत्तर प्रदेश (3.91 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.29 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (0.22 लाख हेक्टेयर), पंजाब (0.16 लाख हेक्टेयर), तमिलनाडु (0.08 लाख हेक्टेयर) और ओडिशा (0.01 लाख हेक्टेयर) राज्यों में अधिक बोवनी कि रिपोर्ट मिली है। महाराष्ट्र (2.16 लाख हेक्टेयर), गुजरात (0.40 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (0.12 लाख हेक्टेयर), बिहार (0.11 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (0.08 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.05 लाख हेक्टेयर) राज्यों से कम क्षेत्रफल की सूचना मिली है।

जूट: पिछले वर्ष की इसी अवधि (6.94 लाख हेक्टेयर) की तुलना में जूट और मेस्टा के तहत लगभग 6.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज की सूचना दी गई है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 0.39 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र कवर किया गया है। मेघालय राज्य (0.01 लाख हेक्टेयर) राज्यों में अधिक बोवनी कि रिपोर्ट मिली हैं। वही बिहार (0.22 लाख हेक्टेयर), पश्चिम बंगाल (0.16 लाख हेक्टेयर), असम (0.03 लाख हेक्टेयर) और ओडिशा (0.01 लाख हेक्टेयर) राज्यों से कम बोवनी की सूचना मिली है।

कपास: पिछले वर्ष की इसी अवधि (120.94 लाख हेक्टेयर) की तुलना में लगभग 119.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास का कवरेज दर्ज किया गया है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 1.73 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र कवर किया गया है। गुजरात (1.60 लाख हेक्टेयर), राजस्थान (1.41 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.36 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.15 लाख हेक्टेयर) और ओडिशा (0.08 लाख हेक्टेयर) राज्यों में अधिक बुवाई कि रिपोर्ट मिली हैं। आंध्र प्रदेश (2.11 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (1.28 लाख हेक्टेयर), पंजाब (0.79 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (0.70 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (0.33 लाख हेक्टेयर) राज्यों से कम बोवनी की सूचना मिली है।

मालवा का ट्री-मैन: फसल गांव के बच्चों को समर्पित

बंजर पहाड़ी पर लगा दिया आम का बाग

रतलाम। जागत गांव हमार

अरुणाचलम के पैडमैन मुरुगनंथम और बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी की तरह ही रतलाम के भेरूलाल धाकड़ भी देश और प्रदेश में ट्री मैन के नाम से मशहूर होते जा रहे हैं। हाथ में फावड़ा लिए सुबह से शाम तक पहाड़ी पर गड्ढा खोदना और उनमें आम की गुठलियों की बुवाई करना भेरूलाल धाकड़ का जुनून बन चुका है। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अब हरे-भरे आम के बगीचे और फलदार वृक्षों से भर गया है। दशरथ मांझी और अरुणाचलम मुरूगनाथम जैसी बड़ी शख्सियतों के साथ इनका नाम इसलिए जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि मेहनत और जुनून के मामले में 62 साल के भेरूलाल भी उन्हीं के जैसे हैं। रतलाम जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर नौगांवा गांव की बंजर पहाड़ी को किसान भेरूलाल ने 10 साल में अकेले ही आम के बगीचों और फलदार वृक्षों से हरा-भरा कर दिया है। अब यहां आम के करीब 500 पेड़ हैं। कई पेड़ों से फल मिलना भी शुरू हो चुके हैं। भेरूलाल इन फलों को बेचते नहीं हैं। गांव के बच्चे और बाहर से आने वाले लोगों को वह आम की यह फसल समर्पित कर देते हैं।

पौधों की सालभर देखरेख

भेरूलाल बताते हैं कि 80 के दशक में खेती से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। तब वह अपने गांव के कुछ लोगों के साथ मजदूरी करने महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र के जलगांव में सभी लोग कुआं खोदने का काम करते थे। वहां के एक बड़े उद्योगपति ने इन सभी लोगों को एक बंजर पहाड़ी पर काम करने के लिए मजदूरी पर रख लिया। उन्हें गड्ढे खोदकर फलदार पेड़ लगाने का काम करना था। 2 सालों तक मजदूरी कर भेरूलाल धाकड़ और उनके साथी मजदूरों ने पहाड़ी को हरा-भरा बना दिया।

पहाड़ी को हरा-भरा करने का प्रण

भेरूलाल धाकड़ को यहीं से मन में प्रेरणा जागी कि वह भी अपने गांव की पहाड़ी को एक दिन ऐसे ही हरी-भरी बना देंगे। गांव वापस आने के बाद वह घर और खेती के काम में व्यस्त हो गए। कुछ साल गुजर जाने के बाद भेरूलाल धाकड़ को एहसास हुआ कि उन्होंने गांव की बंजर पहाड़ी को हरा-भरा करने का प्रण लिया था। इसके बाद भेरूलाल धाकड़ ने बारिश के पूर्व पहाड़ी पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बारिश होते ही इन गड्ढों में इकट्ठा की गई आम की गुठलियां लगा दीं, जिसके बाद वर्षभर आम के पौधों की देखरेख कर पौधों को वृक्ष बनाने अभियान शुरू कर दिया।

पहले सब मजाक उड़ाते थे

भेरूलाल ने अपने इस अभियान के बारे में जिसको भी बताया तो उसने उनका मजाक ही उड़ाया। यहां तक कि परिवार के लोगों से भी उन्हें मदद नहीं मिली। हर कोई उन्हें नजरअंदाज करने लगा। लोग कहते थे कि बंजर पहाड़ी पर फालतू मेहनत कर रहे हो। गांव के बसंतीलाल बताते हैं कि 40 से 45 डिग्री के तापमान में लू के थपेड़ों के बीच भेरूलाल पहाड़ी पर गड्ढा खोदने में व्यस्त रहते थे। पहाड़ी के ऊपर अब पाइपलाइन की मदद से पौधों के लिए पानी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले ऐसा नहीं था।

तत्कालीन कलेक्टर बी चंद्रशेखर से मिली सराहना

ट्री मैन के रूप में अपनी पहचान बना चुके भेरूलाल धाकड़ पहली बार मीडिया के सामने तब आए, जब आम से भरी बोरी लेकर वह तत्कालीन कलेक्टर बी चंद्रशेखर के पास पहुंचे। कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने उनसे पूछा कि इतने सारे आम क्यों लेकर आए हो। भेरूलाल ने कहा कि उनकी सालों की मेहनत का फल है, जिसे वह कलेक्टर को सौंपने आए हैं। कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने नौगांवा पहुंचकर भेरूलाल की इस अथक मेहनत को देखा और सराहा। जिसके बाद कलेक्टर ने उनके साथ गांव के ही लोगों की एक समिति बनवाकर पहाड़ी पर फलदार पौधों का पौधरोपण करने परमिशन दे दी, लेकिन समिति के सदस्यों ने कुछ दिन साथ देकर पहाड़ी पर आना बंद कर दिया। इसके बाद भी भेरूलाल का जुनून और अभियान जारी रहा।

हरी-भरी पहाड़ी देखकर प्रेरणा लें लोग

भेरूलाल धाकड़ कहते हैं कि उनका एक ही सपना है कि यह बंजर पहाड़ी पूरी तरह फलदार पेड़ों से भर जाए और गांव के बच्चे और यहां पर्यटन के लिए आने वाले लोग हर मौसम में किसी न किसी तरह के फल का स्वाद ले सकें। यहां आने वाले लोग निःशुल्क इन फलों को खाए और पेड़ लगाने की प्रेरणा लेकर अपने घर जाए। बहरहाल, आधुनिकीकरण और विलासिता के लिए पेड़ और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग सुकून और शांति ढूंढने अब इन्हीं आम के बगीचों में पर्यटन के लिए पहुंचने लगे हैं। उम्मीद यही की जाती है कि यहां पहुंचकर वह ट्रीमैन भेरूलाल धाकड़ से प्रेरणा ले और पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में तकनीकी प्रशिक्षण का मिला लाभ

वायरस से बर्बाद हुई थी मिर्च, अब 25 क्विंटल एकड़ का उत्पादन

संजय शर्मा। खरगोन

पिछली मिर्च की फसल वायरस के कारण बर्बाद हो गई थी। बर्बाद होने के पीछे के कारणों का पता कुछ किसानों को खरगोन के कृषि मंडी में 16-17 जून को आयोजित हुए किसान सम्मेलन में तकनीकी जानकारियों से लाभ मिला। किसानों ने फिर हिम्मत व कड़ी मेहनत और जोखिम उठाकर बेहतर कीट तथा समय प्रबंधन कर फसल तैयार की। इस वर्ष बोरांवा के कुछ किसानों की यह तकनीक करागर साबित हुई और अब वे हरी मिर्च की बंपर पैदावार ले रहे हैं। यहां के 2 से 5 एकड़ के मिर्च काश्तकार मोतीराम वर्मा, ओमप्रकाश यादव, संजय पाल,महेश यादव, लालखेड़ा के श्याम पवार व अघावन के सदाशिव पाटीदार बताते है कि मिर्च की खेती

जोखिम की हो गई है। पिछले साल वायरस अटैक से घाटा हुआ। इस बार पौधे तैयार कर गर्मी में फसल लगा दी थी। किसान संगोष्ठी व सम्मेलनों की तकनीक सीख काम आई। इस तरह पिछले साल के घाटे को पाटने हरी मिर्च की बंपर पैदावार ले रहे हैं। गर्मी की लगाई मिर्च के फिलहाल 3000 रुपए क्विंटल भाव मिल रहे है। खरगोन, कसरावद व भीकनगांव ब्लॉक से हर पखवाड़ा 30 वाहन इंदौर, खंडवा व खरगोन मंडी मिर्च भेज रहे हैं। जिले में इस बार लगभग 40 हजार हेक्टेयर में फसल लगाई गई है। कृषि व उद्यानिकी अफसरों के मुताबिक अब तक तापमान मिर्च फसल के अनुकूल रहा है। साथ ही तेज बारिश न होने से फसल को नुकसान नहीं है।

हरी मिर्च के भाव घटे तो लाल मिर्च से होगा मुनाफा- किसानों के मुताबिक वातावरण में उमस नही है इसलिए फसल बेहतर है। कीट प्रबंधन में परेशानी नहीं आई। प्रति एकड़ 25000 रुपए तक खर्च आया है। फिलहाल हरी मिर्च के शुरुआती भाव अच्छे हैं। भाव गिरेंगे तो घाटे की स्थिति में लाल मिर्च तैयार करेंगे। बाजार में भी सूखी मिर्च 200-300 रुपए किलो के भाव बिक रही है। अभी दो माह तक लाल मिर्च में तेजी के आसार बने हुए हैं।

प्रशिक्षणों से किसानों को मिलता है लाभ

उपसंचालक कृषि एमएल चौहान बताते हैं पिछले साल वायरस अटैक से फसल को नुकसान हुआ था। कृषि व उद्यानिकी विभाग ने कृषि वैज्ञानिकों के ब्लॉक व जिला स्तर पर तकनीकी सत्र आयोजित किए थे। प्रशिक्षण का किसानों को लाभ मिलता है।

इस पर कृषि विशेषज्ञों ने कराया था ध्यान आकृष्ट

16 से 17 जून को कृषि मंडी में आयोजित हुए किसान सम्मेलन में डॉ. एसके त्यागी ने फसल चक्र का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी थी। साथ ही उन्होंने पौध प्रबंधन के लिए केंचुआ व गोबर खाद की संतुलित मात्रा में उपयोग करने सरिकी टिप्स बताई थी। इसके अलावा उन्होंने नीम की खली 2 क्विंटल प्रति एकड़ व जैविक दवाइयों के उपयोग के बारे में बताते हुए कहा था कि 10 से 15 दिनों में इसका उपयोग करें। उन्होंने जिंक सल्फेट व पौधे रौपने की उचित दूरी व आकार के बारे में बताया था।

धान की सुरक्षा करने में कमजोर साबित हो रहा सरकारी तंत्र

बालाघाट के गोदामों में रखा हजारों बोरी धान-गेहूं सड़ा

बालाघाट। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला धान का कटोरा माना जाता है, जहां के किसान दिन दुगुनी-रात चौगुनी मेहनत करके धान का उत्पादन कर अनाज उगाते हैं और समर्थन मूल्य पर अपनी उपज शासन को बेच देते है। जिसके बाद उक्त अनाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन व जिम्मेदार विभाग के सुपर्द हो जाती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि किसानों द्वारा मेहनत करके उगाया गया अनाज जिम्मेदारों के द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए सड़ा दिया जाता है। यह बात इसलिए कही जा रही है, क्योकि मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन की कई गोदामों व ओपेन कैंपो में भंडारित करके रखा गया हजारों क्विंटल धान इस वर्ष भी खराब हो गया है। जिसकी ताजी तस्वीरें वारासिवनी के खापा ओंपन कैंप व परसवाड़ा स्थित डोंगरिया ओपन कैंप में देखी जा सकती है। जहां वर्ष 2021-22 से भंडारित करके रखा गया हजारों क्विंटल धान सडा दिया गया है। अब इसे जिम्मेदारों की अनदेखी व लापरवाही का परिणाम ही कहा जाएगा। जानकारों की माने तो यह स्थिति समय रहते धान का उठाव व मिलिंग ना होने के चलते देखने मिल रही है। जहां धान का कटोरा कहे जाने वाले बालाघाट जिले के विभिन्न गोदामों और ओपेन कैंपो में भंडारित करके रखा गया धान और गेहूं पुरी तरह सड़ चुका है। यह तस्वीरें

डोंगरिया ओपर कैंप की है, जहां किसानो से समर्थित मूल्य पर खरीदकर करीब 02 हजार बोरीयों में भंडारित करके रखा धान अंकुरित होकर सड़ गया है। जबकि इस मामले में विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि यह अनाज पिछले दो साल से ऐसी स्थिति में पड़ा है। अब इस लापरवाही को लेकर अफसरों को जिम्मेदार ठहरा दें या फिर रख रखाव का अभाव कहकर किसी और के उपर जिम्मेंदारी ठहरा दिया जाए, लेकिन सच तो यह है कि अनाज का एक-एक दाना किसानों की मेहनत का फल होता है।

परसवाड़ा में उठाव ना होने की वजह से खराब हो रहा

यह स्थिति एक मात्र बालाघाट जिले की ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के कई जिलों में यही हालात देखने मिलेंगे। जहां पर समर्थन मूल्य पर किसानो से क्रय किए गए हजारों-लाखों क्विंटल धान रख रखाव के अभाव में सड़ गया है। परसवाड़ा के डोंगरिया स्थित ओपन कैंप में करीब 07 हजार बोरी धान समर्थन मूल्य पर क्रय करके भंडारित रखा गया था। जो समय पर उठाव ना होने की वजह से खराब हो रहा है। जिसका कुछ अंश पूर्णतः खराब भी हो चुका है। जिसको लेकर पूर्व में ही भी **जागत गांव हमार** ने खबर प्रकाशित की थी। मामला शासन-प्रशासन के संज्ञान में लाया था। परंतु किसानों की उपज को लेकर ना तो सरकार गंभीर हुई है और ना ही जिम्ममेदार विभाग। धान की तरह गेहूं की भी स्थिति खराब होने पर पहुंच चुकी थी। जहां हमारी खबर के प्रकाशन के बाद वेयर हांउसिंग लॉजिस्ट कार्पोरेशन के द्वारा शासन के निर्देश पर गेहूं का उठाव कार्य प्रारंभ किया गया है। अब सोसायटीयों के माध्यम से राशन में वितरण करवाया जा रहा है। मप्र राइस मिलिंग की पालिसी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राईस मिलर्सों ने मिलिंग का कार्य बंद कर दिया था। जिस कारण गोदामों और ओपेन कैंप में भंडारित धान का उठाव नहीं हो पा रहा था। परिणाम स्वरूप संग्रहित धान सडने की स्थिति में आ गया है।

अन्न दूत योजना परिवारों में लायी खुशियां

जो युवा पहले दूसरों के घर काम करते थे अब वे स्वयं कहलाएंगे मालिक

खरगोन। मप्र शासन द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन शासकीय उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचाने के लिए सीएम अन्न दूत योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को उचित मूल्य की राशन दुकानों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए चार पहिया वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है। खरगोन जिले में अन्न दूत योजना के तहत खाद्य सामग्री उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचाने के लिए 14 वाहन प्राप्त हुए हैं। 13 अगस्त को जिले के 14 हितग्राहियों को वाहनों की चाबी सौंपी जाएगी। इस योजना से जिले के 14 युवा हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। जिन्हें योजना के तहत वाहन क्रय करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया था। इन वाहनों से उचित मूल्य राशन दुकानों पर राशन सामग्री का परिवहन उठाव निर्धारित मापदंड के अनुसार किया जाएगा। जो युवा अब से पहले अन्य लोागों के घर वाहन या अन्य तरह का कार्य करते थे वे अब अपना वाहन चलाएंगे और मालिक कहलाएंगे। साथ ही योजना का समय पर क्रियान्वयन होगा जिससे अंतिम छोर के व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलेगा। इस योजना से युवाओं का स्वरोजगार स्थापित हुआ ही साथ ही पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा।

अतिरिक्त समय में हितग्राही कर सकेंगे वाहन का निजी उपयोग

3 हजार क्विंटल सामग्री का प्रतिमाह चार हजार किलोमीटर के मान से प्रति वाहन परिवहन अनुमानित है। वाहन मालिक प्रतिमाह 15 से 20 कार्य दिवस के अलावा शेष दिनों में वाहन का निजी उपयोग कर सकेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत योजना अंतर्गत लाभार्थी हितग्राहियों को राशन सामग्री पहुंचाने के लिए 65 रुपए प्रति क्विंटल के मान राशि प्रदाय की जाएगी। हितग्राहियों को राशन के परिवहन के लिए लगभग 7.5 मेट्रिक टन क्षमता वाला वाहन जो कि 25 लाख रुपए में प्रदाय किया गया है। इसमें 1.25 लाख रुपए का भुगतान राज्य शासन द्वारा तथा 1.25 लाख रुपए का भुगतान स्वयं हितग्राही द्वारा किया जा रहा है।

वाहन पहुंचने पर कलेक्टर ने किया अवलोकन

कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने गत दिवस सुबह मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना के तहत जिला मुख्यालय पहुंचे वाहनों का अवलोकन किया। उन्होंने वाहनों का अवलोकन कर वाहन मालिकों से उचित मूल्य दुकानों तक सामग्री पहुंचाने व उठाव करने की जानकारी प्राप्त की। साथ ही कलेक्टर वर्मा ने खाद्य विभाग के अधिकारियों से योजना और उसके क्रियान्वयन की जानकारी भी ली। 13 अगस्त को मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना के तहत खरगोन-बड़वानी सांसद गजेन्द्र सिंह पटेल द्वारा जिले के 14 हितग्राहियों को चाबी सौंपी जाएगी।

मछुआरों और मत्स्य पालकों से मत्स्य बीज का उठाव करने की अपील

बालाघाट। जिले में तालाबों एवं जलाशयों की अधिक संख्या होने और यहां की जलवायु मत्स्यपालन के लिए उपयुक्त होने के कारण बालाघाट जिला मध्यप्रदेश का सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाला जिला है।

यहां पर तालाबों एवं जलाशयों की अधिक संख्या होने के कारण बड़े पैमाने पर मछुआरों द्वारा मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। मत्स्योद्योग विभाग द्वारा मछुआरों को मत्स्य बीज स्पान उपलब्ध कराया जाता है। उप संचालक मत्स्योद्योग शशि प्रभा धुर्वे ने बताया कि चालू वर्ष 2023 में बालाघाट जिले को शासकीय प्रक्षेत्र से 25 करोड़ स्पान मत्स्य बीज

उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र मुरझड़ में मत्स्य बीज का उत्पादन किया जा रहा है। अब तक 13 करोड़ स्पान मत्स्य बीज का उत्पादन कर लिया गया है। मुरझड़ प्रक्षेत्र में उत्पादित मत्स्य बीज स्पान को बालाघाट, बैहर, तिरोड़ी, बम्हनवाड़ा प्रक्षेत्र में मछुआरों को विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। मुरझड़ प्रक्षेत्र से भी मछुआरों को मत्स्य बीज का विक्रय किया जा रहा है। जिले के मछुआरों एवं मछुआ सहकारी समितियों से कहा गया है कि वे अपने निकटवर्ती प्रक्षेत्र पर पहुंच कर रोहू, कतला, मृगल, कामन कार्प का मत्स्य बीज क्रय कर सकते हैं। मत्स्य बीज शासन द्वारा निर्धारित दर पर प्रदाय किया जा रहा है। उपसंचालक धुर्वे ने बताया कि बालाघाट जिले में मनरेगा के अंतर्गत 84 अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गये है। इन अमृत सरोवरों में भी मछली पालन प्रारंभ किया जा रहा है। अमृत सरोवर को मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर लेने वाले मछुआरों, मछुआ सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों से अपील की गई है कि वे शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र से मत्स्य बीज स्पॉन क्रय कर सरोवर में समय पर डालना सुनिश्चित करें।

डीबीटी सलाहकार ने मां दंतेश्वरी हर्बल समूह की उपलब्धियों की मुक्तकंठ से की तारीफ

ग्लोबल मार्केट में धूम मचाएगी बस्तरिया काली मिर्च

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा औषधीय, सगंध पौधों तथा मसालों पर शीर्ष विशेषज्ञों की राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। सेमिनार की विशेषज्ञ आमंत्रित वक्ता मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर चिखलपुटी कोंडागांव की गुणवत्ता तथा विपणन प्रमुख अपूर्वा त्रिपाठी ने बस्तर की ब्लैक गोल्ड कही जाने वाली काली मिर्च की सफल किस्म मां दंतेश्वरी काली मिर्च-16 पर अपनी प्रस्तुति देते हुए बताया कि कैसे डॉ. राजाराम त्रिपाठी के मार्गदर्शन में इस संस्थान द्वारा विकसित बस्तरिया काली-मिर्च एमडीबीपी 16 बस्तर के किसानों की जिंदगी को बदल रही है, बेहतर बना रही है।

नई किस्म नई किस्म प्रति पेड़ 8 से 10 किलो काली मिर्च का उत्पादन दे रही - उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में काली मिर्च का प्रति पेड़ उत्पादन औसत डेढ़ से दो किलोग्राम है जबकि बस्तर में डॉ. त्रिपाठी के द्वारा विकसित यह नई किस्म नई किस्म प्रति पेड़ 8 से 10 किलो काली मिर्च का उत्पादन दे रही है। इतना ही नहीं, इसकी गुणवत्ता भी शेष भारत की काली मिर्च से बेहतर है। उन्होंने सभी आमंत्रित विशेषज्ञों को कोंडागांव चलकर अपनी काली मिर्च की खेती इसके उत्पादन तथा गुणवत्ता को देखने पर रखने के लिए आमंत्रित भी किया।

मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म ने पहली बार देश में उच्च स्तरीय मल्टी-लेयर फार्मिंग शुरू की-

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि संभवत:पूरे देश में पहला है, जिसने इस तरह की उच्च स्तरीय मल्टी-लेयर फार्मिंग शुरू की है। आगे उन्होंने देश के वैज्ञानिकों को छत्तीसगढ़ बस्तर में हो रही काली-मिर्च की सफल खेती की विशिष्ट पद्धति के बारे में बताया। संगोष्ठी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही देश के कुछ अन्य कृषि विश्वविद्याल भी मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप के सहयोग से अपने राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में काली मिर्च की खेती के विस्तार किया जाना तय किया गया। इसका पायलट प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू किया जाएगा।

एथेनो मेडिको गार्डन में लगभग लगभग 340 प्रकार की औषधीय जड़ी-बूटियां संरक्षित

मिजोरम विश्वविद्यालय आइजाल भी काली-मिर्च की खेती में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाएगा इस योजना में मां दंतेश्वरी हर्बल समूह की भी मार्गदर्शक भूमिका व सक्रिय भागीदारी होगी। इस अवसर पर डॉ. राजाराम त्रिपाठी के काली मिर्च के खेतों से सीधा वीडियो प्रसारण संगोष्ठी के वैज्ञानिकों, विभिन्न संकायों के छात्रों , शोधार्थियों तथा उपस्थित प्रगतिशील किसानों को दिखाया गया, जिसे सभी ने बहुत सराहा। डीबीटी-आईएलएस भारत सरकार नई दिल्ली के सलाहकार डॉ. मोहम्मद असलम, जिन्होंने दो दशक पूर्व भी मां दंतेश्वरी फार्म का दौरा किया था, अपने पिछले भ्रमण की यादें ताजा करते हुए वर्तमान में मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म तथा रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित उच्च लाभदायक बहुस्तरीय कृषि के सफल मॉडल को देश की खेती और किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए सराहना की, और इस समूह के साथ मिलकर अंचल के अन्य किसानों को जोड़ते हुए संयुक्त रूप से काली मिर्च की खेती परियोजना शुरू करने की पहल का प्रस्ताव भी रखा। अपूर्वा ने अपने समूह के लगभग 7 एकड़ में पिछले तीन दशकों में जंगल उगाकर तैयार किए गए एथेनो मेडिको गार्डन के बारे में भी बताया, जहां लगभग 340 प्रकार की औषधीय जड़ी-बूटियां संरक्षित हैं और उनमें से लगभग 25 तो विलुप्तप्राय व रेड डेटा बुक में है। अपूर्वा त्रिपाठी ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह बस्तर व छत्तीसगढ़ के लिए विशेष गर्व का विषय है कि, अपने विशिष्ट गुणवत्ता के कारण अल्प समय में ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी धाक जमाने वाली बस्तर की ब्लैक-गोल्ड कही जाने वाली काली-मिर्च की ब्रांडिंग व मार्केटिंग अब एमडी बॉटनिकल्स के तहत की जा रही है और जल्द ही यह बस्तर में किसानों द्वारा उगाए गए हर्बल्स ,मसाले,मिलेट्स के साथ ही काली मिर्च भी बस्तरिया-ब्रांड एमडी बोटैनिकल्स के जरिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन सहजता से उपलब्ध होगा।

प्राकृतिक तरीके से बढ़ता है उत्पादन

बस्तर में काली मिर्च की खेती करने वाले चार बार के सर्वश्रेष्ठ किसान के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉ. राजाराम त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने आस्ट्रेलियन टीक के साथ काली मिर्च की खेती की शुरुआत की, जिससे उत्पादन बढ़ा है। आस्ट्रेलियन टीक में अन्य पौधों की तुलना में करीब 300 गुना नाइट्रोजन की मात्रा को भूमि में संधारित करने क्षमता होती है, जिससे प्राकृतिक तरीके से उत्पादन बढ़ता है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

मुरैना में बनकर तैयार हैं 100 अमृत सरोवर, सार्थक हो रहे हरियाली बढ़ाने और जल संरक्षण के प्रयास

सांसों के स्त्रोत हैं पेड़-पौधे
पानी जीवन का आधार, आइए इन्हें सहेजें

इच्छित गढ़पाले
सीईओ, जिला पंचायत, मुरैना

क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को 24 घंटे में 550 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि एक पेड़ इस अवधि में सिर्फ 55-60 लीटर ऑक्सीजन देता है। इस हिसाब से हरेक व्यक्ति को पर्याप्त ऑक्सीजन के लिए 10 पेड़ की जरूरत है। तो क्या खुद के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन का इंतजाम करना हमारा दायित्व नहीं है। पूरे जीवन काल में 10 पौधे लगाना कोई कठिन काम भी नहीं है। वह भी तब, जबकि शासन-प्रशासन इस काम में सदैव आपके सहयोग के लिए तत्पर है।

पीढ़ियां निर्बाध सांस ले सकें

सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही नहीं, बल्कि अच्छा मानसून भी पेड़-पौधों पर ही निर्भर है। इसके अलावा फल, फूल, औधाधियाड्ड और विभिन्न जरूरतों के लिए लकड़ी भी तो चहिए, इसलिए सरकारी स्तर पर हर साल पौधरोपण कार्यक्रम को एक अभियान की तरह चलाया जाता है। पिछले कुछ सालों में पूरे प्रदेश की तरह मुरैना जिले में भी बड़े पैमाने पर पेड़-पौधे लगाए गए, जिनकी वजह से पर्यावरण में उल्लेखनीय सुधार नजर आने लगा है। हरियाली को और बढ़ाने के लिए इस बार भी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पौधरोपण किया जाने वाला है। देशभर में चलाए जा रहे मेरी माटी, मेरा देश अभियान के तहत जिले के हरेक गांव में 500 पौधे लगाने का संकल्प सरकारी स्तर पर लिया गया है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति को भी पौधरोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यदि सभी जन एक संकल्प के साथ इस अभियान से जुड़कर पौधरोपण में भागीदारी करेगा तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण संतुलित हो जाएगा। तो आइए बारिश के इस मौसम में कम से कम 10 पौधे लगाकर पर्यावरण सुधार के महायज्ञ में आहुति दीजिए। आपके एक छोटे से प्रयास से आने वाली पीढियां निर्बाध सांस ले सकेंगी।

जल संचनाएं बनाने पर जोर

प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण प्रतिकूल ढंग से बदलते पर्यावरणीय परिवेश में जल सहेजना भी हम सबकी महती जिम्मेदारी है। शासन और प्रशासन जल संरक्षण और संवर्धन के लिए भी मनुष्यों व अन्य जीव-जंतुओं के हित में प्रतिबद्ध है। मुरैना जिले को ही लें, जहां एक साल के भीतर जल संरक्षण के सार्थक प्रयास हुए हैं। यहां अमृत सरोवर योजना के तहत अब तक 100 से अधिक तालाबों का निर्माण गांवों में कराया जा चुका है। इसके अलावा 25 से अधिक तालाब अभी निर्माणाधीन हैं। जो तालाब बन चुके हैं, उनमें जल संग्रहण होने भी लगा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जल संरचनाएं बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पानी सहेजने की मुहिम चलाएं

शासन-प्रशासन के इस प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों का जलस्तर ऊपर उठेगा और इसका प्रत्यक्ष लाभ लोगों को मिलेगा। जरूरी यह है कि आमजन भी जल संरक्षण के प्रति जागरुक हों। हम सब खयाल रखें कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले पानी को हम सहेजकर रखें, व्यर्थ न जाने दें। इसके लिए घरों के आसपास सोख्ता गड्ढे बनाए जा सकते हैं। यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में जल संकट जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए, अभी से, इसी वक्त से हम जीवन का आधार कहे जाने वाले पानी को सहेजने में जुट जाएं।

मुरैना के 625 गांव ओडीएफ प्लस की श्रेणी में

देशभर में शिद्दत से चलाए गए स्वच्छता अभियान के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। मुरैना जिले को ही लें, जो पूरी तरह ओडीएफ होने के बाद अब ओडीएफ प्लस पर फोकस कर रहा है। यहां 478 ग्राम पंचायतों के कुल 625 गांवों को ओडीएफ प्लस श्रेणी में लाने के लिए जिला पंचायत ने कदम आगे बढ़ाया है। इसके तहत अभी तक गांवों में 300 सामुदायिक टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा 3500 शोकपिट और नाडेप संरचनाएं तैयार की गई हैं। बता दें कि शोकपिट का उपयोग गीले कचरे के निपटान के लिए किया जाता है, जबकि नाडेप का इस्तेमाल सूखे कचरे को ठिकाने लगाने में होता है। 625 गांवों को ओडीएफ प्लस की श्रेणी में लाना जिला पंचायत की बड़ी उपलब्धि है। खास बात यह कि गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए पंचायत स्तर पर किए गए प्रयासों को ग्रामीणों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। ग्रामीण परिवेश को साफ-सुथरा बनाने के लिए लोग जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों के कार्यों की सराहना भी कर रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)